श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) मार्च, 1990 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गए बीड़ी कर्मकारों की संख्या 21,725 है । क्षेत्र-वार व्याप्ति नीचे दी गई है ।

क्षेत्र का नाम	कर्मकारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2,878
असम	18
बिहार	12,400
कर्नाटक	395
केरल	35
मध्य प्रदेश	1,092
महाराष्ट्र	4,142
राजस्थान	98
तमिलनाडु	569
उत्तर प्रदेश	42
पश्चिम बंगाल	56
कुल:	21,725

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 10 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 589 केन्द्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्रवाई की जाती है ।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजूरी

2252. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **प्रधान मंत्री** 25 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1856 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संबंध में राज्य सरकारों को जारी किये गये निर्देश बीड़ी उद्योग पर भी लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्देशों को विभिन्न राज्यों में बीड़ी उद्योग में लागू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां :

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहित अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और कार्यान्वयन के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही उपयुक्त सरकारें हैं ।

Rehabilitation of Bonded Labour

2253. SHRI JAGADISH JANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether steps have been taken for the Rehabilitation of bonded labour in different States;

(b) if so, the schemes/steps taken in Orissa and other States for the Rehabilitation of bonded labour; and

(c) the outcome of those schemes in last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) For the purpose of Rehabilitation of Bonded Labour the following steps have been taken by the Centre & State Governments:

(i) The Centre has issued a set of guidelines for the purpose of preparing village level schemes for the rehabilitation of Bonded Labour.

(ii) Since 1982-83, Annual targets are fixed for rehabilitation of Bonded Labour in various State Governments in consideration with them. The progress